Current Business Scenario: Opportunities And Challenges Before Young Entrepreneur

Dr. Neeraj Topkhane

EDITORIAL BOARD

Dr. Vivek Sharma
Prof. and Director
CRIM Barkatulla University, Bhopal

Dr. Anand Tiwari
Professor Dept. of Commerce
Govt. Auto. Girls PG College, Sagar

Dr. A. C. Jain
Prof. Dept. of Commerce
Govt. Arts and Commerce College, Sagar

Dr. Sanjeev Dubey
Prof. Dept. of Commerce
Govt. Arts and Commerce College, Sagar

Dr. Rakesh Tiwari
Prof. and Director
Anand Institute of Management, Bhopal

Dr. Sunita Jain
Prof. and Dean-Faculty of Arts
Swami Vivekanand University, Sagar

Dr. Sunita Dixit
HOD Dept. of Management of Commerce
Swami Vivekanand University, Sagar

Published by:
Swami Vivekanand University , Sagar

Current Business Scenario: Opportunities and Challenges Before Young Entrepreneur

- Prof. Neeraj Topkhane

EDITION - 2017

ISBN- 978-81-929700-1-1

Printed By
Swatantra Computer & Printers
Itwari Ward, Sagar (M.P.)
Ph. 07582-243728 Mob. 9981466528

24. An Introduction To The Potential Of Social Networking Sites In Education - Dr. Ankur Goutam 230

25. E-Business - Miss Preeti Kashayap 238

26. Entrepreneurship Education In India - Scope, Challenges And Role Of B- Schools In Promoting Entrepreneurship Education - Mr. Bikash Deb 243

27. Recent And Innovative Practices In Banking - Mr. Neeraj Goutam 263

28. Make In India : Socio-economic Growth In India - Miss Ayushi Khare 277

29. Current Business Scenario: Opportunities & Challenges Before Young Entrepreneur. - Mrs. Amrita 283

30. Entrepreneurship In India And Legal Frameworks & Policies - Mr. Nishant Dubey, Mohani Choudha 290

31. Digital Student Welfare Machine - The Future of Student Experience - Er. Shivam Kumar Choubey 299

32. मेक इन इंडिया : वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का एक प्रयास - डॉ. उतसव आनन्द, मधुकर इटेवार 303

33. "भारतीय व्यापार में भारत निर्माण मिशन की भूमिका" - डॉ. वीरेन्द्र सिंह मटसेनिया 310

"भारतीय व्यापार में भारत निर्माण मिशन की भूमिका"

डॉ. वीरेन्द्र सिंह मटसेनिया

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करते हुये एल्सवर्थ ने बताया कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध भी विभिन्न राष्ट्रों के आपसी आर्थिक संबंधों से है। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसमें आर्थिक संबंधों की शुरूआत होती है और इनके कारण कुछ आर्थिक समस्यायें भी पैदा होती हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक संबंधों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच व्यापार से पैदा होने वाले आर्थिक संबंधों एवं उनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।

परिभाषिक शब्दावली– विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, राजकोषीय, लालफीताशाही, निवेशक, अवस्थापन परियोजना निर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्पेश–वॉक।

शोध पत्र के उद्देश्य–

1. शोध पत्र में विदेशी व्यापार की भूमिका का अध्ययन किया गया है।
2. भारत निर्माण मिशन का भविष्य में व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है।

शोध प्राविधि

शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों को आधार माना गया है। उसी के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषणात्मक अध्ययन–

जिस प्रकार एक व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी पूर्णरूप से आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता है। आज हम भले ही यह कहें कि प्राचीन काल में मनुष्य स्वयं अपनी सारी आवश्यकाताओं की पूर्ति करता था, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उस युग में भी कुछ न कुछ मात्रा में विशिष्टीकरण था। यद्यपि वह अवैज्ञानिक एवं प्रारम्भिक किस्म का था। आज तकनीकी विकास और वैज्ञानिक खोजों ने पूर्ण विशिष्टीकरण को सम्भव बना दिया है।

19वीं सदी तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार का पूर्ण समर्थन किया, बीसवीं सदी में 1930 की व्यापारिक मंदी के आने से व्यापार अधिक प्रभावित हुआ। राश्ट्रों को आर्थिक दृष्टि से पंगू बना दिया और वे संरक्षण की नीति अपनाने लगे। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है, कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो गया। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समय के साथ–साथ महत्वपूर्ण बदलाव आये। शुरूआत में पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यापार बढ़ाने में अपना योगदान दिया, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में पूंजीवाद का बोलवाला था, लेकिन आज विश्व पूंजीवाद एवं साम्यवाद में बंट गया है इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नई विचारधारा पैदा हुयी है। आज प्रत्येक देश अपने–अपने हितों को ध्यान में रख कर व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जिससे व्यापार में अनेक समस्यायें पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिये आज प्रत्येक देश अपने–अपने तरीके से व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के लिये प्रयास कर रहा है, उसी रास्ते पर भारत भी चलने का भरसक प्रयास कर रहा है।

भारत निर्माण मिशन एक विकास की धारणा है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 सितम्बर 2014 को शुरू किया जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों के निवेश को आकर्षित करना है जिससे भारत एक विनिर्माणघर के रूप में विकसित हो सके। यह भारत का आर्थिक रूपान्तरण सुनिश्चित करेगा तथा अवांक्षित

ISBN- 978-81-929700-1-1

कानूनों तथा अवरोधों को दूर करेगा इसके कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस योजना को 25 क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। जैसे:–

1. ऑटो मोबाइल्स
2. ओटो मोबाइल कम्पोनेट्स
3. वायुयान (Aviation)
4. जैब प्रौद्योगिकी (Bio-Technology)
5. रासायनिक, रसायन (Chemicals)
6. निर्माण कार्य (Construction)
7. रक्षा उत्पाद (Defence Manufacturing)
8. विद्युत सामान (Electrical Machinery)
9. इलैक्ट्रॉनिक व्यवस्था (Electronics Systems)
10. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)
11. संचार तकनीक और व्यवसाय व्यवस्था प्रक्रिया (Information Technology and Business Process Management)
12. चमड़ा (Leather)
13. संचार माध्यम एवं मनोरंजन(Media and Entertainment)
14. खदान (Mining)
15. तेल और गैस (Oil and Gas)
16. दवाईयाँ(Pharmaceutical)
17. बन्दरगाह एवं पानी के जहाज(Ports and Shipping)
18. रेल(Railway)
19. नवीनीकरण ऊर्जा (Renewable Energy)
20. सड़क और मार्ग (Roads and Highways)
21. अंतरिक्ष (Space)
22. कपड़ा और वस्त्र (Textiles and Garments)

ISBN- 978-81-929700-1-1

23. ऊष्मा विद्युत (Thermal Power)
24. पर्यटक, अतिथि (Tourism and Hospitality)
25. स्वास्थ्य (Wellness)

इन सभी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सरकार ने दी है। जबकि अन्य तीन क्षेत्रों में निवेश की स्थिति इस प्रकार है :—

Space - 74%

Difene - 49% News Media 26%

इसके लिये आठ सदस्यीय एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है, जो 48 घण्टे में निवेशकों की पूछताछ तथा समस्याओं का समाधान देगा वह भारतीय नीतियों को निवेशकों को स्पष्ट करेगा और पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान करेगा जिससे निवेशक राज्यों एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत भारी मात्रा में निवेश करने को उत्साहित हो। मिशन का पवित्र उद्देश्य यह है कि हमारे यहां विश्व के किसी भी देश से निवेश के लिये वहत्तर अवसर एवं परिस्थितियाँ है हम निवेशकों के लिये बहुत उदार हुये हैं। अपनी नीतियों निवेशकों के हित में किये है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत निर्माण मिषन ने विश्व के निवेशकों का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया है इससे घरेलू एवं विदेशी निवेशकों में एक सकारात्मक एवं प्रभावी सन्देश गया है और प्रधानमंत्री जी ने निवेशकों के फायदे के लिये सरकारी नीतियों में बदलाव, उदारीकृत राजनीतिक व्यवस्था, राजकोषीय, मौद्रिक तथा औद्योगिक वातावरण तथा हर सम्भव रियायतें, सुविधाऐं, समुचित आधारभूत ढांचा तथा लालफीताशाही मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराने का वायदा किया है।

इस शोध पत्र में मैंने केवल शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखा है, जब भारत शिक्षा एवं अनुसंधान के द्वारा ''मेक इन इन्डिया'' को अपनायेगा तो हम कम से कम समय में भारत के विकस के सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है

ISBN- 978-81-929700-1-1

जिसके द्वारा हम आपात पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, और निर्यात को बढ़ा कर अपनी भुगतान सन्तुलन की असामान्य स्थिति को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि इससे रोजगार के नये अवसरों को बढ़ा सकते हैं और जनसंख्या को उसकी रूचि के अनुसार कृषि क्षेत्र से निकालकर औद्योगिक क्षेत्र में लगा सकते हैं। वर्तमान में भारत विश्व के देशों में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है यहां की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग युवा है। इस आबादी के उचित प्रयोग द्वारा भारत विश्व में अपनी पहचान बना सकता है साथ ही साथ अपनी आर्थिक उन्नति भी कर सकता है।

भारत का आर्थिक विकास विनिर्माण क्षेत्र के विकास के बिना नहीं हो सकता है। यहां हम एक उदाहरण द्वारा भारत के विकास में इसके योगदान को समझ सकते हैं जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय उत्पाद आई–फोन को लेते हैं एक आई–फोन का मूल्य सामान्यतय 500 अमरीकी डॉलर है लेकिन उसके निर्माण में केवल 7 डोलर खर्च आता है 175 रूपये उसके कल–पुर्जे और उसकी प्रणाली पर ओर 319 डालर उसकी डिजाइन और आई.पी.आर. सेल्स और वितरण पर खर्च आता है। यदि हम 319 रूपये में से 50 प्रतिशत खर्च केवल डिजाइन और बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर माने। इस स्थिति में हम अगर किसी भी उत्पाद के डिजाइन और बौद्धिक सम्पदा अधिकार में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं तो हमारी अर्थव्यवसथा में हमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं क्योंकि किसी भी उत्पाद पर डिजाइन एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम "मेक इन इन्डिया" मिशन में विनिर्माण के साथ ही डिजाइन और बौद्धिक सम्पदा अधिकार को षामिल कर लिया जावे तो भारत को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि भारत उत्पादन करने में सक्षम तो होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ बहतु बड़ा उपभोक्ता बाजार भी होगा तो हमें बहुत ही सस्ती दर पर वस्तुयें प्राप्त हो सकती हैं और भारतीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है।

यह हमारा सौभाग्य है कि भारत ने पिछले तीन दशकों से

ISBN- 978-81-929700-1-1

उत्पादों की डिजाइन में अच्छी पहचान बनाई है। लेकिन यह कार्य हम अपने लिये न करते हुये ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये करते आ रहे हैं। बहुत से डिजाइन केन्द्र भारत में ही स्थित हैं। फिर भी भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम उत्पाद बनाने एवं व्यापार करने में अपनी क्षमता का प्रयोग करने लगे तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा और हमें भी इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा और रक्षा एवं आंतरिक और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील विषयों पर हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। इन सब से विदेशी बाजार में हमारी छवि भी सुधरेगी और भारत को नया बाजार मिलने लगेगा। हमारी गिरती मुद्रा की छवि भी सुधरेगी और आंतरिक रूप से हम सशक्त भी होंगे।

भारत की स्थिति–

भारत ने तीन दशक से डिजाइन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। 1980 में भारत में केवल 100 इन्जीनियरिंग कॉलेज थे, इनके द्वारा केवल एक वर्श में 20,000 से भी कम इंजीनियर बन कर निकलते थे । गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिये इन्जीनियर बनाना दूर का सपना होता था। 1980 के बाद भारत में निजी क्षेत्र के कॉलेज आने लगे और साथ ही साथ सरकार ने भी सरकारी कॉलेज खोल दिये, आज भारत में 4000 से भी अधिक इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें प्रतिवर्ष 15 लाख छात्र प्रवेश लेते हैं।

आज भारत में 20 आई.आई.टी. तथा 30 एन.आई.टी., आई. आई.आई.टी., आई.एस.ई.आर. और एन.आई.एस.ई.आर. जैसी संस्थायें तकनीकी शिक्षा दे रही हैं। आज यांत्रिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 25 प्रतिशत गरीब छात्र एवं 25 प्रतिषत छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से इन्जीनियर बन रहे हैं। इसके बाद भी उच्च शिक्षा तकनीक का विकास नहीं हो पा रहा है। आज कुछ उच्च संस्थान जेसे आई. आई.टी. और कुछ अन्य संस्थाओं को छोड़ दे तो बाकी सभी संस्थाओं में शिक्षा का स्तर निम्नतर है इस हेतु मानव विकास संसाधन मंत्रालय आगे के 10 वर्षों में गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किये हैं। शिक्षकों की

ISBN- 978-81-929700-1-1

पर्याप्तता एवं उनको उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब होने के बाद भी भारत उत्पादों का मालिक नहीं बन पाया है न ही व्यावार में भागीदारी बढ़ा पाया है हम आज भी डिजाईन का काम सेवा के रूप में ही कर रहे हैं। भारत निर्माण मिषन के माध्यम से भारत को कल–पुर्जा उद्योग को विकसित करना होगा इसके लिये हमें स्वयं ही डिजाइन करनी होगी और विपणन की स्थानीय व्यवस्था को मजबूत करना होगा। आज भारत इस क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा है हम संचार उद्योग और मोबाईल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विदेषी बाजार में उतरने को तैयार हो चुके हैं। इससे भारतीय डिजाइन एवं कलपुर्जे उद्योग को बढ़ावा मिलने लगा है। आज हमारी सरकारें भी इस ओर ध्यान देने लगी हैं। निवेषकों को उचित माहौल देने को तत्पर हो रही हैं।

आज भारत को अपनी डिजाइन एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार के महत्व को समझना ही होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में उसके पास अपार क्षमताऐं है। हमारे वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है विश्व का कोई भी वैज्ञानिक मिशन भारतीयों वैज्ञानिकों के बिना पूरा नहीं हो पा रहा है फिर भी हमें उन्हें बेहतर नेतृत्व देने की जरूरत है। भारतीय शिक्षाविद् अनुसंधान एवं विकास कार्यों से इतने सन्तुष्ट है कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार के महत्व को नहीं समझते हैं, ना हीं वे अपने शोध कार्य को ठीक से प्रकाशित ही करवाते हैं। वे इसके महत्व को नहीं जान पाये हैं कि व्यक्तिगत बौद्धिक सम्पदा अधिकार कितना विकास में येागदान करता है।

इसके महत्व को समझाने के लिये शिक्षाविदों को तकनीकी निकायों से जोड़ने की आवश्यकता है जिससे उनके योगदान का सही–सही मूल्यांकन किया जा सके। एक बार किसी का बौद्धिक सम्पदा अधिकार पंजीकृत हो जाता है तो इसका मूल्य बढ़ जाता है और प्रत्येक व्यापारिक उधम को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अनुसार उत्पाद बनाना पड़ता है इसके लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकार के

स्वामी से सहमति भी लेनी पड़ती है।

विकसित देशों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार को बढ़ावा देने के लिये समिति बनी हुयी है जो बौद्धिक सम्पदा अधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है और इन समितियों का सहयोग सरकारें करती हैं

इस प्रकार की समितियां कोरिया, चीन, कनाडा, जापान, यूरोप आदि देषों में दूरसंचार मानक विकास पर समिति है। भारत ने भी 2013 से दूरसंचार क्षेत्र में दूरसंचार मानक विकस समिति का गठन किया है। इस समिति से भारतीय शिक्षाविदों को सहयोग प्राप्त होगा। आज आवश्यकता है कि अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी पहल की जाये, जिससे भारतीय योग्यता को पहचान मिल सके, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त हो। इसके लिये भारतीय शिक्षाविदों एवं उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा जैसा कि वर्तमान प्रयासों से हो रहा है इसको और अधिक मजबूती देने की जरूरत है।

मानव विकास संसाधन मंत्रालय को सभी षिक्षण संस्थाओं को शोध एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, देश की प्रयोगशालाओं जैसे सी.डी. ओटी, सी.डी.एसी और सी.एस.आई.आर. इसके अतिरिक्त डी.आर.डी.ओ., परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग की प्रयोगषालाऐं भी हैं। इन प्रयोगशालाओं द्वारा कुछ उत्पाद तो बनाये जाते हैं लेकिन उनका स्तर इतना नहीं है कि उनका भारत वाणिज्यक लाभ ले सके। आज पूरे शिक्षाविदों को इस क्षेत्र में अपना नजरिया बदलने की जरूरत है जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सकें।

हमारे शिक्षाविद् ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये डिजाइन एवं उत्पाद का कार्य करते हैं जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक है। कहीं शिक्षाविदों का तो यहां तक कहना है कि हम डिजाइन एवं उत्पाद के क्षेत्र में पष्चिमी देषों की तुलना में आधी कीमत में ही यह काम कर सकते हैं लेकिन हमें बेहतर वातावरण नहीं मिल पाता है।

ISBN- 978-81-929700-1-1

जिसके कारण हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग देश हित में नहीं कर पा रहे हैं।

आज हमारे शिक्षाविद् भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये विदेषों में ऊँचे पेकेज को ठुकराकर देश में स्टार्टअप्स को चुन रहे हैं। आई. आई.टी. के छात्र इसमें अपनी अंग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्पेष एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद एवं भारत में अन्य स्थान पर भी स्पेश सेन्टरों को विकसित कर रहा है। जिससे अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो रहा हैं। अंतरिक्ष में लैब स्थापित करने के लिये योजना बना रहा है। भारत में अभी हाल ही में 20 देश के 97 उपग्रहों को अन्तरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल की है। भारत सरकार भी अब इस क्षेत्र को फायदे का सौदा समझकर अधिक बजट आवंटन करने जा रही है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार का हिस्सा बढ़ेगा जिससे हमारा भुगतान सन्तुलन की स्थिति में भी सुधार हो सकेगा और भारत दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा देष बन कर उभरेगा ऐसी हम आषा करते हैं।

सन्दर्भ सूचीः

1. योजना मासिक पत्रिका भारत सरकार।
2. सिंह, रमेश –भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकाशन टाटा मेग्राहिल्स, नई दिल्ली।
3. स्वामी, के.डी.–अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
4. राणा, के.सी. – अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

ISBN 978-81-929700-1-1